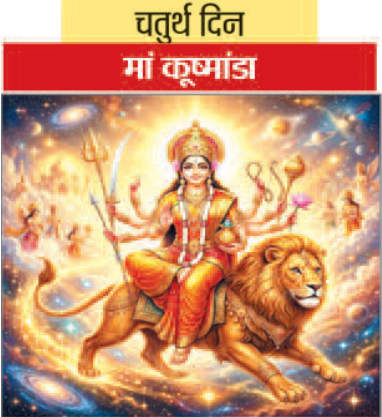




मां कूष्मांड को सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। अष्टभुजा देवी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, ऊर्जा, समृद्धि और उत्साह प्राप्त होने की मान्यता है। भवत जीवन में खुशहाली के लिए इनका आशीर्वाद मांगते हैं।

संक्षिप्त

समाचार

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई रुकी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह केस 20 18 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयानों से जुड़ा है। मामला महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने



महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामलों की कुल संख्या 16 है।

इसमें से 15 मामले उन्होंने अपने 2024 के लोकसभा चुनावी हलफनामे में घोषित किए हैं, और 1 मामला पूर्ण में सावरकर परिवार द्वारा वापस किया गया है। राहुल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी- राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार किया था। राहुल गांधी की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुराने फेसलों का हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले ही स्पष्ट हो चुका है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल की याचिका पर गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त 2019 के आदेश को बरकरार रखा था।

चीन ने लददाख की 28 जगहों को अपना बताया

बीजिंग/नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन ने लददाख की 28 जगहों के नाम तय करने के भारत के फैसले पर आपत्ति जताई है। चीन ने मंगलवार को कहा कि ये इलाके उसके हैं और भारत के नाम बदलने या रखने से जमीन पर मालिकाना हक नहीं बदलेगा। भारत ने 2 अक्टूबर को इन जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर तय किए थे। इनमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके भी शामिल हैं, जहां 2020 में भारतीय और



चीनी सैनिकों के बीच तनाव हुआ था। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा कि चीन लददाख को भारत की ओर से बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश नहीं मानता। चीन ने भारत के इस कदम को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि सीमा के पश्चिमी हिस्से के ये इलाके उसके हैं। माओ के मुताबिक, भारत के इस कदम से सीमा के पश्चिमी हिस्से में उन इलाकों पर चीन का दावा नहीं बदल सकता, जिन्हें वह अपना क्षेत्र मानता है। भारत के गृह मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को लददाख की 28 जगहों और क्षेत्रों के नाम आधिकारिक तौर पर तय किए थे। भारत का फैसला 2023 में चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने के जवाब में उठाया गया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को 'जंगनान' यानी दक्षिणी तिब्बत कहता रहा है। भारत सरकार का कहना था कि उसका मकसद इन जगहों की पहचान को साफ करना है।

भारत ने दुनिया को सस्ती दवाएं और टैलेंट दिया

पीएम मोदी ने कहा-बदले में क्रेडिट-रॉयल्टी भी नहीं ली

देश पहली बार ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का मेजबान

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सस्ती दवाओं से लेकर प्रतिभा तक, दुनिया भारत पर भरोसा करती है। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, लेकिन कभी इसका श्रेय या रॉयल्टी नहीं मांगी। दिल्ली में पहली बार हो रहे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में मोदी ने 25 मिनट स्पीच दी। कहा कि भारत की ताकत दूसरों को सक्षम बनाने में है। उन्होंने डिजिटल तकनीक, वैक्सीन सप्लाई, आर्थिक सुधारों और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका का जिक्र किया। तीन दिन का यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर को खत्म होगा। इस साल फोरम की थीम 'बदलती दुनिया में ताकत के नए स्रोत तय करना' है।

सरकार का उद्देश्य नागरिकों को निर्भर बनाना नहीं- मोदी ने कहा- सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उसका उद्देश्य अपने नागरिकों को व्यवस्था पर निर्भर बनाना नहीं होना चाहिए। बल्कि, उसका उद्देश्य अपने



नागरिकों को सशक्त और सशक्त बनाना होना चाहिए, और भारत इसी राह पर चल रहा है। पीएम बोले- भारत की 7.8 फीसदी ग्रोथ रही है। आज हमारा फॉरेन रिजर्व 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। भारत का कॉन्फिडेंस

ऊंचाई पर है। हमने इन्फ्लेक्सी लॉ बनाया है। बिजनेस से जुड़ी छोटी-मोटी गलतियों को डिस्टेबलाइज किया है। रिफॉर्म्स हमारा कन्विकशन है। पीएम ने कहा- इतिहास में अनेक वैश्विक संगठन बने।

उनके अपने-अपने हित रहे हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट जैसे इनीशिएटिव लिए। भारत किन विचारों को लेकर सामने आया, ये सबके सामने है। भारत जोड़ने और जुड़ने पर बल देता है। पावर दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात करता है। पीएम मोदी ने कहा- जब दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन की जरूरत होती है, तब यह भारत से आती है। जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है, तब भारत के युवाओं पर भरोसा होता है। ये स्पष्ट है कि दुनिया को एक स्टीडी पिलर की जरूरत होती है, तब भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है।

पीएम बोले- अवसर पैदा करें, देशों को जोड़े

ज्ञान, धन और शक्ति का महत्व इस बात में है कि उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता है। भारत दूसरों के लिए अवसर पैदा करने और देशों को जोड़ने में विश्वास रखता है। कोविड के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पहुंचाई। भारत अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल पूरी मानवता के फायदे के लिए करना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सप्लाई चेन, ऊर्जा, खनिज और तकनीक भी देशों के बीच दबाव बनाने के साधन बन रहे हैं। दुनिया को भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है। सरकार का उद्देश्य लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक में भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। स्टार्टअप के मीके छोटे शहरों तक पहुंचे हैं। आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की विकास दर 7.8 फीसदी रही और विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से ज्यादा है। कारोबार को आसान बनाना और सुधार करना सरकार की प्रतिबद्धता है।

एसआईआर के खिलाफ

विपक्ष की याचिका में 14 खामियां

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बताया-कोर्ट फीस 220 रुपए कम दी

पेज भी गायब, मल्लिकार्जुन खड़गे को आईडी कार्ड धुंधला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत 11 विपक्षी नेताओं की ओर से दायर एसआईआर याचिका में करीब 14 खामियां बताई हैं। यह याचिका एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी है। इन खामियों के कारण मंगलवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रजिस्ट्री ने याचिका के साथ जमा किए गए दस्तावेजों में भी खामियां बताईं। कुछ पन्ने पढ़ने लायक नहीं हैं, जबकि कुछ पन्ने गायब हैं। इसके अलावा, कोर्ट फीस भी 220 रुपए कम जमा की गई है।



रजिस्ट्री ने कुल 14 खामियां दर्ज की हैं। रजिस्ट्री ने कहा है कि याचिका दाखिल करने वाले वकील से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन

राहुल बोले- ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे,जितना समय लगे, आंदोलन जारी रहेगा

एसआईआर के खिलाफ और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडी ब्लॉक के नेताओं ने राहुल गांधी के घर चाय पर बैठक की। करीब दो घंटे चली इस बैठक के बाद सभी नेता एक साथ बाहर आए और मीडिया को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना हमारा मिशन है।

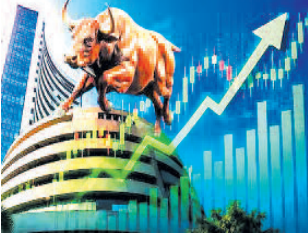
खड़गे के पहचान पत्र (आईडी कार्ड) की साफ कॉपी मांगी है। इसके अलावा, 9 याचिकाकर्ताओं से याचिका दायर करने के लिए लिखित सहमति भी मांगी है। 12 अक्टूबर को दायर याचिका में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को पक्षकार बनाया गया है।

रजिस्ट्री ने कुल 14 खामियां दर्ज की हैं। रजिस्ट्री ने कहा है कि याचिका दाखिल करने वाले वकील से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन

आसमान पर सेंसेक्स 1100 अंक तक उछला

शेयर मार्केट की बुल रफ्तार, बम-बम रहा बाजार

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू शेयर बाजार में गजब की तेजी दिखी है। मार्केट बंद के दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1109.10 अंक यानी कि 1.54 फीसदी बढ़त के साथ रहे



निशान में 73,033.78 पर बंद हुआ। वहीं, 50 शेयरों निफ्टी 358.60 अंक यानी कि 1.60 फीसदी चढ़कर 22,721.95 पर बंद हुआ। मार्केट बंद के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में

से 27 में तेजी और सिर्फ तीन शेयरों में गिरावट दिखी। इनमें टॉप गेनर एचसीएल टेक में 8.28 फीसदी की तेजी और टॉप लूजर कोटक महिंद्र बैंक में 0.90 फीसदी की गिरावट दिखी। मार्केट की इस बढ़त में निवेशकों की संपत्ति में करीब 3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच सेंसेक्स पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर अब 469 लाख करोड़ रुपये हो गया है। बीते कारोबारी सत्र यानी कि 12 अक्टूबर सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला था, जबकि इसकी क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई थी। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 400 अंकों की तेजी के साथ 72,771.32 पर खुला था, लेकिन जब बंद हुआ तो यह अपने डे हाई से करीब 950 अंक लुढ़क गया।

केंद्रीय मंत्री मुरुगन का इस्तीफा

राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ी



समय देना चाहता हूं। मुरुगन ने लिखा, 'आपके नेतृत्व में देश और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। वे गरीब परिवार से आते हैं और उनके माता-पिता मजदूरी करते थे।' तमिलनाडु के रहने वाले मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था।

पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा, 6 लोगों की मौत

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के मुल्तान में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा हुआ है। ये हादसा तब हुआ, जब रहमान बाबा एक्सप्रेस पटरियों से उतर गई। इस घटना में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि स्थानीय प्रशासन ने की है। वहीं 40 से ज्यादा लोग इस एक्सप्रेसीडेंट में घायल हुए हैं।

ओवैसी की समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ पर अटैक

आजमगढ़ को कमी मुलायम सिंह यादव ने बनाया था अमेद!

लखनऊ/आजमगढ़ (एजेंसी)। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नौ दिनों तक इंतजार किया और फिर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा ने यूपी विधानसभा चुनावों में तालमेल के उनके खुले ऑफर को ठुकराया तो ओवैसी ने भी जैसे अबकी बार उनकी चुनावी जड़ें ही उखाड़ने की ठान ली है। अ स द्द दी न ओवैसी ने सपा और अखिलेश यादव को टारगेट करने के लिए सबसे पहले आजमगढ़ चुना है, जिसे मुलायम सिंह यादव ने तीन दशकों से ज्यादा समय तक अपना अभेद्य किला बनाकर रखा था। एआईएमआईएम एम्पी असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों से कहा है कि वे यादव परिवार की लाल टोपी को गुलामी करना बंद कर दें। ओवैसी ने यह आह्वान आजमगढ़ की सभा में किया, जिसे सपा का गढ़ माना जाता है।



मुरिलम नेतृत्व की बात कहकर सपा को चुनौती- आजमगढ़ में जाकर ओवैसी का यह कहना कि मुसलमान अब नेता बनने की तैयारी करें, क्योंकि उन्होंने जिन दलों के लिए सीढ़ियां लगाईं, उन्होंने कभी भी उन्हें उनका वाजिब हक नहीं दिया। इसके लिए उनके निशाने पर सपा ही नहीं, बसपा और कांग्रेस है। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि यूपी के मुसलमान उन मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव की खिदमत में पीढ़ियां लगा दीं, लेकिन उन्होंने किसी मुसलमान को प्रमुख नेता बनने का मौका नहीं दिया।

ई- कचरा: आधुनिक युग की एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती

(लेखक- सुनील कुमार महला)

(14 अक्टूबर दिवस विशेष आलेख)

आज विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, चार्जर, बैटरी, प्रिंटर और अन्य विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जब ये उपकरण पुराने हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, तो इनसे ई-कचरा पैदा होता है। गौरतलब है कि खराब मोबाइल फोन के अलावा पुराने इयरफोन, यूएसबी कैंबल, रिमोट, खिलौने, छोटे पंखे और बिजली से चलने वाले अन्य उपकरण भी ई-कचरे में शामिल हैं। आज धरती पर ई-कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है और यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। कहना गलत नहीं होगा कि यदि इन उपकरणों का समय पर सही तरीके से निपटान नहीं किया जाए, तो ये मिट्टी, पानी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूँ कि पुराने और बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित निपटान, पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ई-कचरा दिवस मनाया जाता है। वास्तव में, इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि पुराने मोबाइल, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कैंबल और बैटरी को सामान्य कूड़े में फेंकने के बजाय उचित संग्रह केंद्रों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि उनका सुरक्षित पुनर्चक्रण किया जा सके। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। इसकी शुरुआत अपशिष्ट विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोरम ने की थी। वास्तव में, यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संगठन की स्थापना वर्ष 2002 में बैलजयम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुई थी।

हाल फिलहाल, इसमें कोई संदेह या दोराय नहीं है कि विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इनसे जुड़े उपकरणों का गलत तरीके से निपटान पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में सीसा और पारा जैसे हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, जो

मिट्टी और पानी को दूषित कर सकते हैं। दूसरी ओर, इसी कचरे में सोना, तांबा और एल्युमीनियम जैसी कीमती धातुएँ तथा कई उपयोगी पदार्थ भी पाए जाते हैं, लेकिन इन पदार्थों को पुनर्चक्रण के माध्यम से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे जहां एक ओर प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है, वहीं पर नए कच्चे माल(रा-मैटिरियल) की आवश्यकता कम होती है। ई-कचरे को खुले में जलाने या असुरक्षित तरीके से तोड़ने से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अधिकृत संग्रह केंद्रों या पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुँचाए और मनुष्यों, अन्य जीवों तथा प्रकृति के स्वास्थ्य की रक्षा में योगदान दे।

ई-कचरे की स्थिति- विश्व और भारत-

संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट-2024 के अनुसार, वर्ष 2022 में दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन टन यानी 6.2 करोड़ टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति औसतन 7.8 किलोग्राम ई-कचरा पैदा हुआ। चिंताजनक बात यह है कि कूल ई-कचरे में से केवल 22.3 प्रतिशत का ही औपचारिक रूप से संग्रह और पुनर्चक्रण किया गया। शेष लगभग 77.7 प्रतिशत ई-कचरे का उचित प्रबंधन नहीं हो सका और उसका बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रों या कचरा भराव स्थलों तक पहुँच गया। इतना ही नहीं, आज हमारा देश भारत भी ई-कचरे की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित है। दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद भारत को ई-कचरा उत्पन्न करने वाले प्रमुख देशों में तीसरे स्थान पर बताया जाता है। भारत में ई-कचरे की मात्रा के संबंध में लगभग 4.5 मिलियन टन यानी 45 लाख टन प्रतिवर्ष का आँकड़ा सामने आया है। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में ई-कचरे का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कबाड़ी और अन्य लोगों द्वारा संसाधित किया जाता है। उपलब्ध अनुमानों में यह हिस्सा लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक बताया गया है। इस काम में सुरक्षा के उचित उपाय नहीं अपनाए जाने पर काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। ई-कचरे की बढ़ती मात्रा इस समस्या को और गंभीर बना रही है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2010 से 2022 के बीच ई-कचरे में हुई वृद्धि की दर उसके औपचारिक संग्रह और पुनर्चक्रण की वृद्धि दर से लगभग पाँच

गुना अधिक रही। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर-2024 के अनुमान के अनुसार, यदि यही स्थिति बनी रहैी, तो वर्ष 2030 तक दुनिया में ई-कचरे की मात्रा बढ़कर लगभग 82 मिलियन टन यानी 8.2 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो सकती है।

ई-कचरा कम करने के लिए क्या करें?

भारत जैसे तेजी से डिजिटल होते देश में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, घरेलू उपकरणों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ई-कचरे को के वल सफाई की समस्या मानना उचित नहीं है। यह पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, जनस्वास्थ्य और जिम्मेदारी के साथ उपभोग करने से जुड़ा विषय है। वास्तव में, ई-कचरे को कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए। मोबाइल फोन, लैपटॉप या अन्य उपकरणों में छोटी-मोटी खराबी आने पर उन्हें फेंकने के बजाय उनकी मरम्मत करानी चाहिए। केवल नया मॉडल आने या फैशन के कारण पुराने उपकरणों को बदलने से बचना चाहिए। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सामान्य कूड़े में डालने के बजाय अधिकृत ई-कचरा संग्रह केंद्रों या संबंधित निर्माता की वापसी योजना के माध्यम से पुनर्चक्रण के लिए देना चाहिए यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अभी भी इस्तेमाल करने योग्य है, तो उसे जरूरतमंद व्यक्ति को देकर या दान करके उसका उपयोगी जीवन बढ़ाया जा सकता है। नए इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करते समय उसकी गुणवत्ता, टिकाऊपन और मरम्मत कराने की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। पुनर्चक्रण के लिए मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य उपकरण देने से पहले उनमें मौजूद निजी जानकारी को सुरक्षित तरीके से मिटाना भी आवश्यक है।



अंत में यही कहा जा सकता है कि ई-कचरे की समस्या का समाधान केवल सरकार या पुनर्चक्रण केंद्रों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें कम खरीदने, उपकरणों का लंबे समय तक उपयोग करने, खराब होने पर उनकी मरम्मत कराने और बेकार होने पर उचित पुनर्चक्रण अपनाने की आदत डालनी होगी। हमारी छोटी-छोटी जिम्मेदारियाँ पर्यावरण को सुरक्षित रखने, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ धरती देने में बड़ा योगदान दे सकती हैं। वास्तव में, हमें जरूरत के अनुसार कम से कम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहिए, उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहिए, खराब होने पर मरम्मत करानी चाहिए और बेकार होने पर सही तरीके से उनका पुनर्चक्रण करना चाहिए।

(सुनील कुमार महला, फीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार।)

(यह लेखक के व्यक्‍तिकत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‍ निवार्य नहीं है)

वोट चोरी के आरोप: राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का षडयंत्र!

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में और दिल्ली में बड़े पैमाने पर विशेष प्रदर्शन का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है।मतदाता सुचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और कथित तौर पर योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाने को लेकर विवाद है।सोमवार को इंडिया ब्लाक ने कनाटपलेस से सुप्रीम कोर्ट तक एक विरोध मार्च भी निकाला और चीफ जस्टिस से मिलने का प्रयास किया।चीफ जस्टिस ने मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इस पर अदालत से बाहर मिलना चर्चा करना न्यायिक मर्यादा के खिलाफ बताया।

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा पिछले कुछ महीनों में एसआइआर प्रक्रिया से जुड़े फैसलों पर आपत्ति जताए जाने की खबरें सामने आई थीं।विपक्ष और विभिन्न संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

इंडिया ब्लाॅक द्वारा संसद से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकाला गया है, जिसमें राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए हैं।

दिल्ली में संसद भवन और जंतर-मंतर के पास हस्तकृ तथा अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

मुंबई के शिवाजी पार्क और अन्य हिस्सों में भी आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों ने प्रदर्शन किया है।नुवाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया और नए कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में को वारंटो याचिका भी दायर की गई है।

बढ़ते विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कुछ चुनावी दौरे स्थगित किए गए हैं और चुनाव आयोग के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जिस तरह आक्रामकता दिखा रहा है वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने जैसा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र की मांग को लेकर धरना व रौप प्रदर्शन कर रही काॅकरोच जनता पार्टी और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा एसआईआर के विरोध में निकाला रौप प्रदर्शन और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पार्षदपति से मिलकर ज्ञानेश कुमार विरुद्ध कारवाई की मांग करने के बीच देश के 124

पूर्व आई.ए.एस., आई.एफ.एस. व आई.पी.एस. तथा अन्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों ने भी देश के जनसाधारण के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिस में चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन निरीक्षण का समर्थन किया गया है।

पत्र में उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का आकलन राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी चुनाव आयोग के तहत केंद्र में सतारूढ़ भाजपा ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हार का सामना किया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा अर्धना पूर्ण बहुमत खो बैठी थी। उस समय चुनावी प्रक्रिया पर जीतने वाले पक्ष ने कोई शिकायत नहीं की थी। भारत सरकार के पूर्व सचिवों, राजदूतों, पुलिस महानिदेशकों, राज्य के मुख्य सचिवों और आयकर विभाग के पूर्व महानिदेशकों समेत इन उच्च पदस्थ रहे अधिकारियों ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गलतियों को सुधारा जाना चाहिए लेकिन इससे एसआइआर की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एसआइआर का उद्देश्य अपात्र मतदाताओं को हटाना है। इस प्रक्रिया में कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन यह भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

बूथों पर कब्जे, मतपेटियों में अपने पक्ष में मतपत्र दूंसने और चुनावी हिंसा के दौर से भारत के बदलाव का जिक्र करते हुए अधिकारियों ने कहा कि आज की चुनावी व्यवस्था में कई स्तरों पर जांच और सुरक्षा उपाय हैं। इनमें मतदान एजेंट, ईवीएम को सील करना, स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा और वीपीपेट से सत्यापन शामिल हैं। उन्होंने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव का हवाला दिया, जिसमें दोबारा मतदान की नौबत नहीं आई और 1951 के बाद सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया।पूर्व अधिकारियों ने एसआइआर को मतदाता सूची को दुरुस्त करने और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने की आवश्यक प्रक्रिया बताया। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं और सात लाख दोहरी प्रविष्टियों की पहचान की गई।

पूर्व अधिकारियों ने कहा- हम किसी दल से नहीं जुड़े हैं। हम इसलिए पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि बिना पर्याप्त सुबूतों के चुनावों को बार-बार धांधलीपूर्ण बनाने से लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआइआर किसी को मतदाता सूची से बाहर

उत्सव है बुद्धत्व

बुद्धत्व मौलिक रूप से प्राति है, विद्रोह है, बगावत है। काशी के पंडितों की सभा प्रमाणपत्र थोड़े ही देगी बुद्ध को! बुद्धपुरुष तुम्हें पोप की पदवियों पर नहीं मिलेंगे और न शंकराचार्यों की पदवियों पर मिलेंगे। क्योंकि ये तो परंपराएं हैं। और परंपरा में जो आदमी सफल होता है, वह मुर्दा हो तो ही सफल हो पाता है। परंपरा के द्वारा पद पाना सिर्फ मुर्दों के भाग्य में हैं, जीवित लोगों के नहीं। यह सौभाग्य है जीवितों का और मुर्दों का दुर्भाग्य। इसलिए तुम कैसे पहचानोगे? और पूरी पहचान का तुम विचार ही मत करना। क्योंकि तुम पूरा पहचानोगे तो तुम बुद्ध हो जाओगे और तुम बुद्ध होते तो पहचानने की जरूरत न थी। तुम नहीं हो, इसीलिए तो पहचानने चले हो।

इसलिए पूरे-पूरे का खयाल मत करना। छोटा सा टुकड़ा चांदनी का तैर आ तुम्हारे पास, तो बहुत धन्यभाग! अहोभाग! तुम उतने ही पर भरोसा करना। उस चांदनी के टुकड़े को पकड़ कर अगर बढ़ते रहे, चलते रहे, तो किसी दिन पूरे चांद की भी मालिक हो जाओगे। किसी दिन पूरा आकाश भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा है; लेकिन अभी तुम्हें पहुंचना नहीं आया, चपनी नहीं आया। अभी तुम घुटने के बल चलते हुए छोटे बच्चे की भांति हो। अभी तुम्हें चलने का अभ्यास करना है।

करने का हथियार नहीं है। मसौदा मतदाता सूची अस्थायी होती है और इसमें नाम न होने का मतलब नाम काटा जाना नहीं है। नोटिस और सुनवाई के बिना किसी का नाम नहीं हटाया जाता। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र उन लोगों से कमजोर होता है, जो बिना सुबूत के पॉलीटिकल नैरेटिव गढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर चुनावी व्यवस्था के जरिये लोगों द्वारा खारिज किए जाने के बाद प्रारंभिक बने रहने की कोशिश है।गौरतलब है कि इससे पूर्व 42 पूर्व न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला पत्र लिखा था। सीजीपी और विपक्षी दलों के नेता देश की व्यवस्था को कमजोर करने व देश की साख व छवि को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, यह देश हित में नहीं है। एक लोकतांत्रिक सरकार जो देश के संविधान अनुसार काम कर रही है उसके प्रति भ्रम व भ्रतिया पैदा करना लोकतंत्र के हित में नहीं है। विपक्षी दलों को जहां अपनी कमजोरियों के लेकर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, वहीं भाजपा व मोदी सरकार की नीतियों से भी सीखने की आवश्यकता है। विपक्षी दल जिस तरह देश में एक नकारात्मक राजनीति माहौल बनाकर स्थापित सरकार व व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, उससे देश में अराजकता का माहौल बरगमा जो आम आदमी सहित किसी के भी हित में नहीं होगा।

सरकार की नीतियों का विरोध करना विपक्षी दलों का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना जिसके वह स्वयं एक महत्वपूर्ण अंश हैं, अनुचित है। धरने व प्रदर्शन विपक्षी दलों की हताशा को दर्शाते ही हैं, साथ में जन साधारण की रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा करते हैं। भीड़तंत्र को लोकतंत्र पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो यह स्थिति अराजकता वाली ही होगी तथा जिस की लाठी उसकी भैंस वाली जंगल राज स्थापित होगा, भारत विरोधी शायद यही चाहते हैं।

सवाल यह है कि काकरोच पार्टी को आगे कर क्या विदेशों से संचालित भारत विरोधी कतरे भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैला कर भारत को कमजोर करने के मंछले को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी दल इस में सहयोगी बन कर अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। यह बेवद्द शर्मनाक और खतरनाक अजेंडा है इस को हर कीमत पर नकारना होगा। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

संपादकीय

ट्रंप के भ्रम

इसमें दो राय नहीं कि कथित रूप से विश्व की महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका के भ्रम भी बड़े हैं। ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ की तर्ज पर दुनिया को हांकने वाले ट्रंप द्वारा रूसी डीजल खरीदने के निर्णय ने अमेरिका को एक बार फिर दुनिया में बेनकाब किया है। यह विवेचना है कि रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर पच्चीस फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। अब वही ट्रंप जब घरेलू राजनीति की मुश्किलों में खिरे तो उन्होंने यूक्रेन युद्ध की तमाम नैतिक दलीलें ताक पर रख अब रूस से डीजल खरीदने का फैसला कर लिया। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि पिछले दिनों ट्रंप ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी थी, जिसमें भारत व चीन के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर सी फीसदी टैरिफ लगाने का प्रावधान था। ये अमेरिका के दोहरे चरित्र को ही उजागर करता है। यह सर्वविदित है कि अमेरिका की तमाम नीतियां ‘अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका पर खत्म हो जाती हैं।’ ‘पल में तोला, पल में माशा’ वाले ट्रंप के बयानों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। कब वे अपनी पहली बात से मुकर जाएं, कहना कठिन है। उनके भ्रामक बयानों ने पूरी दुनिया में अमेरिका की विश्वसनीयता को रसातल में पहुंचा दिया है। ट्रंप पहले दलील देते रहे हैं कि रूस से पेट्रोलियम पदार्थों को खरीदने का मतलब है कि यूक्रेनियों के संहार के लिये संसाधन उपलब्ध कराना। अब जब अमेरिका रूस से डीजल खरीदेगा तो क्या उससे रूस की आक्रामकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा? लगातार यूक्रेन के समर्थन में बयानबाजी करने वाले ट्रंप ने अब डीजल खरीदने के लिये ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जैलेन्स्की पर बड़ा हमला बोला है। अब वे उन्हें शांति के रास्ते में बाधक बता रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अब यूक्रेन को अपना राष्ट्रपति बदल लेना चाहिए। उनके इस बयान से दुनिया व नाटो में खलबली मच गई है। यानी ट्रंप अमेरिकी डीजल जरूरतों के लिये यूक्रेन पर युद्ध खत्म कराने के लिये दबाव बना रहे हैं। दरअसल, ट्रंप की रूस से तेल खरीदने की नीति में आए बदलाव की असली वजह अगले माह अमेरिका में होने वाले चुनाव हैं। अमेरिका में डीजल के दामों में आई तेजी से नुनाधार उनके खिलाफ हो रहा है। ईरान से जारी युद्ध के चलते पूरी दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत ही नहीं, तमाम यूरोपीय देश भी इस संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन ट्रंप को सिर्फ अपने देश में होने वाले मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल करने की चिंता है। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ अमेरिका में तेजी से गिरा है। आखिर भारत जैसे देश भी वैश्विक तेल संकट में ऐसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। ईरान संकट के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सवाल यह है कि फिर कोई संयु्ध राष्ट्र अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिये रूस या अपनी सुविधा के देश से कच्चा तेल क्यों न खरीदे? आखिर तेल खरीद को लेकर अमेरिका के लिये अलग और अन्य देशों के लिये अलग मापदंड क्यों बनाये जा रहे हैं? आखिर भारत व चीन आदि की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? जाहिरा तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का दबाव भारत के लिये भी उतना ही है। भारत जैसे देश के लिये तो यह चुनौती और बड़ी है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के 88 फीसदी पेट्रोलियम पदार्थ विदेशों से आयात करते हैं। वैसे तो अमेरिका दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है। बहरहाल, इस घटनाक्रम का एक सुखद पहलू यह भी है कि वैश्विक बाजार में रूसी तेल-डीजल खरीद पर प्रतिबंध हटने से इसकी वैश्विक उपलब्धता में वृद्धि होगी। जिससे इसकी कीमतों में स्थिरता आएगी।



13 करोड़ मतदाताओं की नाराजगी: एसआईआर पर अग्निपरीक्षा

(लेखक- सनत जैन)

मतदाता सूची से नाम हटाने का विवाद अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों, लोकतांत्रिक विश्वास और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही का बड़ा सवाल बन गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा लगभग 30 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में नामों को लेकर विवाद तेज हो गया है। दावा किया जा रहा है, अब तक 13 करोड़ 37 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि, हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं और पात्र नागरिकों की अलग-अलग संख्या और उसकी सूची को सार्वजनिक होना चाहिए था, जो चुनाव आयोग ने नहीं किया। लोकतंत्र में पारदर्शिता भी आवश्यक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में दस्तावेजों की अनिवार्यता को लेकर लोगों की परेशानियों और विरोध के

आरोप सामने आए हैं।

महाराष्ट्र में 2 करोड़ 6 लाख, कर्नाटक में एक करोड़ 7 लाख, तेलंगाना में 73 लाख 39 हजार, दिल्ली में 47 लाख 56 हजार तथा आंध्र प्रदेश में 44 लाख 89 हजार मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। इसमें गरीब मजदूरों, प्रवासी परिवारों और कमजोर तबकों के लिए रोजी-रोटी छोड़कर दस्तावेज जुटाना तथा अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना आसान नहीं है। दिल्ली में जब बड़े-बड़े लोगों के नाम भी कट गए उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। अब उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी धर्म विशेष के नागरिकों के चुनिंदा तरीके से नाम काटे गए हैं तो उनके भी नाम जोड़े जाएंगे। मतदाता सूची की शुद्धता के नाम पर किसी भी पात्र नागरिक के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा भारी विरोध होने के बाद विशेष अभियान चलाने की बात कही जा रही है। सवाल है, कि पहले नाम हटाने की नौबत ही क्यों आई? नागरिकों को

अपना मताधिकार बचाने के लिए इतनी मशक़्त क्यों करनी पड़ रही है? सुधार की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें गलत नाम हटें, लेकिन पात्र मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे। संविधान के मौलिक अधिकार कायम रहें।

कंप्यूटर के हवाले मताधिकार कैसे? मतदाता सूची का पुनरीक्षण कानून के अनुसार होना चाहिए। किसी मतदाता का नाम हटाने की प्रक्रिया में लागू नियमों के मुताबिक नोटिस, जवाब और सुनवाई का अवसर महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रणाली प्रशासनिक काम को तेज कर सकती है, वह कानूनी जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकती है। यदि निर्वाचन अधिकारियों को पोर्टल पर काम करने में कठिनाई हुई या निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वचालित प्रणाली पर निर्भर हो गई, तो इसकी जांच व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। नागरिकता की जांच और मतदाता सूची का पुनरीक्षण अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर और फॉर्म-6 को लेकर हुई कार्यवाही तथा आदेशों का विवरण जनता के सामने आना चाहिए। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना होगा, उसकी कार्रवाई किस कानूनी प्रावधान के

तहत की जा रही है। प्रभावित नागरिकों के पास शिकायत तथा अपील के क्या रास्ते हैं।

विपक्ष को मिला बड़ा राजनीतिक मुद्दा- दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़े प्रदर्शन की खबरों ने इस विवाद को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल अपने-अपने रायों में इस मुद्दे को जनता के बीच तले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों के विरोध आरोपों का जवाब देने का मामला नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आयोग की ओर से किसी भी राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र होकर पारदर्शी कार्रवाई होना लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है।

देरी हुई तो संघट गहरा सकता है- पश्चिम बंगाल और बिहार में मतदाता सूची से नाम हटने के कारण राशन तथा

अन्य सरकारी सुविधाएं बंद होने के आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। मतदाता सूची में नाम और सरकारी योजनाओं की पात्रता अलग-अलग विषय हैं। किसी नागरिक को केवल मतदाता सूची में नाम न होने के कारण दूसरी सुविधा से वंचित किया गया है, तो संबंधित नियमों और आदेशों की पड़ताल जरूरी है। सरकार और चुनाव आयोग को तत्काल राज्यवार आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। हटाए गए नामों का कारण, नए मतदाताओं के लंबित आवेदन, बहाली की स्थिति और शिकायतों के निपटारे की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विशेष शिविर लगे और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की समयबद्ध व्यवस्था बने। जनता का आक्रोश जब संस्थागत रास्तों से समाधान नहीं पाता, तब असंतोष बढ़ने का खतरा रहता है। भीड़ का अनियंत्रित होना किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नया संकट है। इसलिए सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका को नागरिकों की शिकायतें सुनने तथा कानूनसम्मत समाधान सुनिश्चित करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय

हैदराबाद (एजेंसी)। यहां हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इस मैच में दोनों ही टीमों जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगी। भारतीय टीम अभी सीरीज में 2-1 से बढ़त पर है। ऐसे में उसका लक्ष्य इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना रहेगा। वहीं मेहमान टीम वेस्टइंडीज भी इसे जीतकर वापसी करना चाहेगी। भारतीय टीम ने लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में जीत दर्ज की थी जबकि रांची में खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने जीत दर्ज की थी। उस मैच में वेस्टइंडीज टीम ने 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की। वहीं तीसरे टी20 में भारतीय टीम ने 148 रनों से जीत हासिल की। अब चौथा टी20 हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

गौरतलब है कि राजीव गांधी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रहती है। पिच सपाट है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। ऐसे में चौथा टी20 भी बड़े स्कोर वाला होने के संकेत हैं। यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को चाहिए कि 210-220 रन बनाए जाए।

वहीं अगर रिकार्ड की बात करें तो इस स्टेडियम में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। यहां कुल 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। इसमें भारतीय टीम ने तीनों में जीत दर्ज की है। ऐसे में इस बार भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है।

दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रिकार्ड भी काफी दिलचस्प रहा है, जिसमें भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस फॉर्मेट में अब तक कुल 35 बार भिड़त हुई है। इन 35



मुकाबलों में से 22 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जो उनकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम ने 11 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला था। यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय टीम

वेस्टइंडीज पर टी20 में ऐतिहासिक रूप से हावी रही है, लेकिन हाली के प्रदर्शन ने मेहमान टीम के आत्मविश्वास को काफी बढ़ाया है। ऐसे में वह कोई कसर नहीं रखेगी।

टीम इस प्रकार है

भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजु सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अश्वर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अशंदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर

वेस्टइंडीज टीम- शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), आमिर जागू (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरन हेटमायर, अकोल हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफन रदफोर्ड, क्रेंटन सैमसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर

गंभीर टीम में जरूरत से अधिक बदलाव कर रहे : वॉटसन

मुम्बई (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर जिस प्रकार से टीम में लगातार बदलाव कर रहे हैं। वह सही नहीं है। वॉटसन के अनुसार हद से ज्यादा बदलाव होने से खिलाड़ी अपनी भूमिका ठीक से समझ नहीं पाते हैं इससे एक बार फिर गंभीर के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे हैं। वॉटसन के अनुसार कि इसी कारण भारतीय टीम के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी नजर आती है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण बल्लेबाजी क्रम के साथ ही खिलाड़ियों में बार-बार बदलाव किया जाना है। इस पूर्व ऑलराउंडर ने हालांकि माना है कि कुछ उभरते खिलाड़ियों का समर्थन करने से लाभ भी मिला है। इन खिलाड़ियों ने बेहतर परिणाम दिये हैं।

गौरतलब है कि गंभीर के भारतीय टीम का में भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने के बाद से ही टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप का खिताब जीता है। इन सफलताओं के बावजूद, भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन कमजोर रहा है। इसे घेरलू मैदान पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, इसी साल भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय सीरीज में भी हार मिली। पिछले एक साल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम को हार खेनी पड़ी है।



इस साल जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भी भारतीय टीम हारी है। वॉटसन ने कहा कि टीम में लगातार बदलाव होने से खिलाड़ियों के लिए अपनी भूमिका समझना और एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाना कठिन होता है। साथ ही कहा कि जब बल्लेबाजी क्रम में बार-बार बदलाव होता है और खिलाड़ी लगातार टीम में आते-जाते रहते हैं, तो टीम का प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। वॉटसन के अनुसार भारतीय टीम के हालिया उतार-चढ़ाव के पीछे भी यही कारण है। वॉटसन ने गंभीर के काम को सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में गंभीर ने कई अच्छी चीजें भी जोड़ी हैं। खिलाड़ियों पर भरोसा जताना उनकी सकारात्मक रणनीतियों में से एक है। वॉटसन के अनुसार, गंभीर ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजु सैमसन का लगातार समर्थन किया और सैमसन ने टी20 विश्व कप के अहम मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके इस भरोसे को सही साबित किया। इससे पता चलता है कि खिलाड़ियों को अवसर देना और उन पर भरोसा बनाना टीम के लिए लाभकारी हो सकता है।

धोनी का आईपीएल में खेलना उन्हीं पर निर्भर :काशी



चेन्नई । आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी में अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है। उन्होंने संकेत दिया है कि धोनी 2027 में टीम के लिए एक बार फिर उतर सकते हैं। धोनी को आईपीएल 2026 में चोटिल होने के कारण एक भी मैच नहीं खेलने की वजह से लीग से बाहर रहना पड़ा था, जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। इसी को लेकर काशी ने साफ किया कि धोनी का खेलना पूरी तरह से उन्हीं के फैसले पर निर्भर करेगा। साथ ही कहा कि फ्रेंचाइजी प्रबंधन ने यह फैसला पूरी तरह से उन पर छोड़ दिया है। विश्वनाथन ने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जो आपको उससे पूछना चाहिए । मुझे भी उससे पूछना होगा। जब वह चेन्नई आते हैं तो वह हमें अपने फैसले के बारे में बताते हैं। उन्होंने अगर कहा, मुझे लगता है कि उनके सीएसके के लिए खेलते रहने के अवसर हैं। गौरतलब है कि 45 साल के हो चुके धोनी की अनुपस्थिति ने उनके आगामी आईपीएल सीजन में खेलने पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, टीम के पूर्व खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुरेश रैना ने धोनी को एक और आईपीएल सीजन के लिए वापसी करते देखने की अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की है। रैना ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से धोनी से आईपीएल 2027 के लिए वापसी करने की गुजारिश की थी। रैना ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आपने आईपीएल 2026 मिस कर दिया है। इसे गिना नहीं जाएगा। आपको अगले साल वापस आना होगा। रैना का मानना ​​है कि धोनी ने वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। यह उनका निजी फैसला होगा, लेकिन रैना को लगता है कि धोनी सकारात्मक हैं और वापसी के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा, टीम भी फिर से अच्छी तरह से घुल-मिल रही है। फैंस भी चाहते हैं कि वह आए।

शमी ने रणजी में शानदार प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं पर भी निशाना साधा

मुम्बई (एजेंसी)। बंगाल की ओर से खेलते हुए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं पर निशाना साधा है। शमी ने न केवल अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया, बल्कि अपनी फिटनेस और टीम इंडिया में वापसी को लेकर दिए गए बयानों से भी सुर्खियां बटोरें, जिनमें इशारों-इशारों में चयनकर्ताओं पर भी तंज कसा। दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में, शमी ने अपनी पुरानी लय में लौटते हुए 17.3 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने 9 मेडन ओवर भी फेंके, जिससे मुकाबले की पूरी टीम महज 240 रनों पर सिमट गई। शमी की यह धारदार गेंदबाजी उनकी फिटनेस और फॉर्म का स्पष्ट प्रमाण थी, जिससे



उनके अनुभव और कौशल की झलक साफ दिखाई दी।

दिन का खेल समाप्त होने के बाद जब शमी से उनकी फिटनेस को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने

जवाब दिया। शमी ने कहा, ‘आप मेरी फिटनेस देख रहे हैं, लिख दीजिए। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे कहने से क्या होगा? मैं मैदान पर हूँ, खेल रहा हूँ और जहां भी मौका मिल रहा है, वहां खेल रहा हूँ।’ उनके इस जवाब से साफ था कि वह अपनी बातों से नहीं, बल्कि मैदान पर अपने प्रदर्शन से अपनी फिटनेस साबित करना चाहते हैं। फिटनेस के अलावा, शमी से यह भी पूछा गया कि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें भारतीय टीम में क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके जवाब में शमी ने चयनकर्ताओं पर तंज कसते हुए कहा, ‘मैं अच्छे गेंदबाज नहीं हूँ। शायद वे वजह रही होगी।’ शमी के इस कटाक्ष भरे बयान से उनकी निराशा और टीम में नहीं चुने जाने की पीड़ा साफ झलक रही थी। यह बयान स्पष्ट रूप से उन

चयनकर्ताओं को संबोधित था जो उनके शानदार घरेलू प्रदर्शन के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं शमी ने चार साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए भी खुशी जाहिर की। शमी ने भुवनेश्वर को लेकर कहा, ‘भुवी की पहले ही वापसी हो जानी चाहिए थी। द्रिस्त य है कि वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रतिभा को लंबे समय तक रोक जाए। यह उनके लिए अच्छा है। उन्होंने आईपीएल में लगातार अच्छे प्रदर्शन किया है और वह इसके हकदार हैं।’ शमी का यह बयान न केवल साथी खिलाड़ी के प्रति सम्मान दर्शाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से यह भी संकेत देता है कि कभी-कभी मुखर न होना भी चयन प्रक्रिया में बाधा बन सकता है।



भारतीय टीम की फील्डिंग को बेहतर बनाने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा : श्रीधर

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व फील्डिंग कोच और श्रीधर का मानना ​​है कि टीम की फील्डिंग को और बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के साथ ही उनके काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शीर्ष स्तर हासिल किया है। वहीं फील्डिंग के क्षेत्र में वह अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंची है जैसी उससे अपेक्षा है। श्रीधर ने कहा, फील्डिंग में खिलाड़ियों की जवाबदेही बढ़ाने के साथ ही नियमित और केंद्रित अभ्यास तथा प्रदर्शन के स्पष्ट मानक तय करने होंगे।

श्रीधर ने माना है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम की फील्डिंग का स्तर उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है। उनके मुताबिक, भले ही हाल ही में टीम ने एक टी20 विश्व कप जीता हो, लेकिन फिर भी मैदान पर कई मौकों पर फील्डिंग में कमियां दिखाई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक क्रिकेट, विशेषकर टी20 प्रारूप में, फील्डिंग को बल्लेबाजी और गेंदबाजी जितनी ही



प्रार्थमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन कैच या स्टैंक रनआउट मैच का रुख बदल सकता है।

श्रीधर ने कहा कि हाल के टी20 मुकाबलों के दौरान भारतीय टीम ने कुल 58 कैच छोड़े हैं। टीम की कैच पकड़ने की सफलता दर महज 73.4 प्रतिशत रही है, जो शीर्ष 10 टीमों में दूसरे

सबसे निचले स्थान पर आती है। इन गंभीर गलतियों का टीम पर सीधा असर पड़ा है। जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी अच्छी फील्डिंग से 129 रन बचाए, वहीं कैच छोड़ने और मैदान फील्डिंग की गलतियों के कारण 226 अतिरिक्त रन विपक्षी टीम को मिले, जिससे टीम को कुल 97 रनों का नुकसान हुआ। इसके

अतिरिक्त, भारतीय खिलाड़ियों ने 19 रनआउट के सुनहरे अवसर गंवाए, जबकि केवल 14 बार ही विपक्षी बल्लेबाजों को रनआउट किया जा सका।

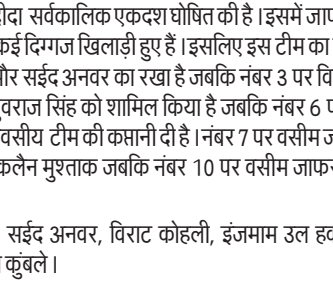
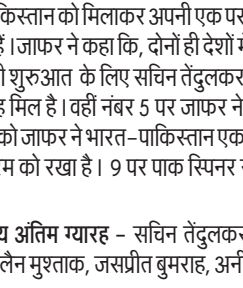
श्रीधर ने घरेलू क्रिकेट व्यवस्था से भी इस दिशा में गंभीरता से काम करने की अपील की, जिससे टीम में शामिल होने वाले नए खिलाड़ियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ-फील्डिंग में भी मजबूत बनाया जा सके।

न्यूजीलैंड दौर को भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए श्रीधर ने कहा कि वहां का उंचा मौसम और तेज हवाएं फील्डिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल खुद को जल्द ढालना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आधुनिक क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन गेंद तक पहुंचने की गति, एक्शन टाइम, कैच पकड़ने की सफलता दर और थो की स्टैकता जैसे आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

जाफर ने अपनी पसंदीदा भारत-पाक अंतिम ग्यारह में 6 भारतीय व 5 पाक खिलाड़ी रखे

मुम्बई । पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारत-पाकिस्तान को मिलाकर अपनी एक पसंदीदा सर्वकालिक एकदश घोषित की है। इसमें जाफर ने 11 में 6 खिलाड़ी भारत के जबकि 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के रखे हैं। जाफर ने कहा कि, दोनों ही देशों में कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं। इसलिए इस टीम का चयन करना उनके लिए बेहद कठिन रहा है। इस टीम में जाफर ने पारी की शुरुआत के लिए सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर का रखा है जबकि नंबर 3 पर विराट कोहली है। जबकि नंबर चार पर पाक के इंगमाम उल हक को जगह मिल है। वहीं नंबर 5 पर जाफर ने युवराज सिंह को शामिल किया है जबकि नंबर 6 पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जगह मिली है। धोनी को जाफर ने भारत-पाकिस्तान एकदिवसीय टीम की कप्तानी दी है। नंबर 7 पर वसीम जाफर ने पाक ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक जबकि नंबर 8 पर वसीम अकरम को रखा है। 9 पर पाक स्पिनर सकलैन मुश्ताक जबकि नंबर 10 पर वसीम जाफर को और नंबर 11 पर जाफर ने अनिल कुंबले को शामिल किया है।

वसीम जाफर की भारत-पाकिस्तान एकदिवसीय अंतिम ग्यारह - सचिन तेंदुलकर- सईद अनवर, विराट कोहली, इंगमाम उल हक, युवराज सिंह, धोनी (कप्तान), अब्दुल रज्जाक, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, जसप्रीत बुमराह, अनील कुंबले।



शुभमन सबसे अधिक पांच बार प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाले भारतीय बने



दुबई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट के टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान शुभमन गिल ने को पांचवीं बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा, जिसके साथ वह इस अवार्ड को सबसे ज्यादा बार जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।

शुभमन की यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेटर्स के बीच उन्हें एक अलग ही मुकाम पर स्थापित करती है। जहां वह अकेले पांच खिताब के साथ शीर्ष पर काबिज हैं, वहीं दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर दो-दो खिताब के साथ मौजूद हैं। वहीं हैरानी की बात है कि दुनिया के

सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल विराट कोहली ने यह सम्मान सिर्फ एक बार ही हासिल किया है। कोहली के अलावा, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, यशस्वी जयसवाल, मोहम्मद निर्रज, अभिषेक शर्मा और संजु सैमसन जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने भी एक-एक बार इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया है।

शुभमन गिल के पांच प्लेयर ऑफ द मंथ खिताबों में जनवरी 2023, सितंबर 2023, फरवरी 2025, जुलाई 2025 और सितंबर 2026 के अवार्ड शामिल हैं, जो उनकी अद्भुत निरंतरता और भविष्य की क्रिकेट में उनके संभावित दबदबे की ओर इशारा करते हैं।

अल्कराज की हार के बाद ज्वेरेव ने रचा इतिहास, पहली बार ATP Year End नंबर-1 रैंकिंग हासिल की

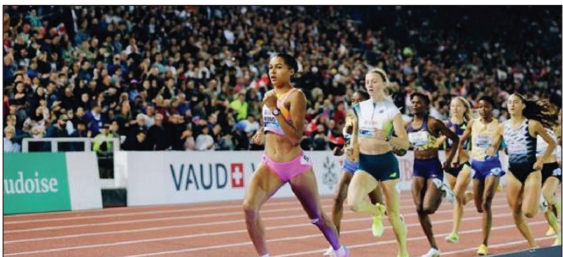


शंघाई। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2026 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पहली बार ATP Year-End नंबर-1 रैंकिंग हासिल करना सुनिश्चित किया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज को शंघाई मास्टर्स में मिली चौकाने वाली हार के बाद ज्वेरेव का साल का शीर्ष रैंकिंग वाला खिलाड़ी बनना तय हो गया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बनेंगे।

29 वर्षीय अलेक्जेंडर ज्वेरेव के लिए यह उपलब्धि उनके शानदार 2026 सीजन में एक और बड़ी कामयाबी है। साल के अंत की ATP रैंकिंग की तारीख 23 नवंबर 2026 को उनकी उम्र 29 साल और 217 दिन होगी। इस तरह वह पहली बार वर्ष के नंबर-1 खिलाड़ी बनने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी भी बन जाएंगे।

ज्वेरेव पहली बार साल के नंबर-1 खिलाड़ी बनने के मामले में अमेरिका के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगुसी से तीन दिन बड़े होंगे। अगुसी ने 1999 में 29 साल और 214 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। ज्वेरेव की यह कामयाबी उन्हें टेनिस इतिहास में एक खास स्थान दिलाएगी।

डायमंड लीग 2027 : 7 मई से दोहा में होगा आगाज, ज्यूरिख में खेला जाएगा फाइनल



दोहा । 2027 डायमंड लीग सीजन की शुरुआत 7 मई को कतर की राजधानी दोहा में होगी। विश्व एथलेटिक्स की इस प्रतिष्ठित ट्रैक एंड फील्ड सीरीज का 18वां संस्करण लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 से लगभग एक साल पहले आयोजित किया जाएगा। दुनिया के शीर्ष एथलीट इस सीजन में अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। 2027 डायमंड लीग का पहला मुकाबला 7 मई को दोहा में आयोजित होगा। इसके बाद सीरीज एशिया के अन्य शहरों की ओर बढ़ेगी, जहां शंघाई/केकियाओ और शियामेन में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शुरुआती मुकाबलों में एथलीटों को तप सीजन में अपनी लय और फॉर्म साबित करने का मौका मिलेगा। डायमंड लीग का रोमांच 3 जुलाई को अमेरिका पहुंचेगा, जहां यूजीन, ओरेगन में प्रतिष्ठित पीपीटी-न वलार्सिक आयोजित होगा। यह मुकाबला सीजन के अहम पड़ावों में से एक होगा। इसके बाद सीरीज एक बार फिर यूरोप लौटेगी, जहां कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अमेरिकी में मुकाबले के बाद डायमंड लीग का आयोजन मोनाको, लुसाने, लंदन, सिलेसिया और ब्रुसेल्स में होगा। इन प्रतियोगिताओं में एथलीटों के पास अंतर्जट्टाक फाइनल के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका रहेगा। सीजन के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन करना खिताबी मुकाबले तक पहुंचने के लिए अहम होगा। 2027 डायमंड लीग का फाइनल 25 और 26 अगस्त को रिवटनजरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित किया जाएगा। दो दिनों तक चलने वाले इस मुकाबले में सीजन के शीर्ष एथलीट डायमंड लीग ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। फाइनल के साथ ही इस प्रतिष्ठित सीरीज के विजेताओं का फैसला होगा। डायमंड लीग का फाइनल बीजिंग में 10 से 19 सितंबर तक होने वाली 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से कुछ सप्ताह पहले आयोजित किया जाएगा। ऐसे में एथलीटों के लिए यह सीजन बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी का महत्वपूर्ण अवसर होगा। लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 से पहले भी यह सीरीज खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखने का अहम मंच बनेगी।

रियाद में मिसाइल हमले के कारण मैच में आई बाधा, रोनाल्डो की अल नासर जीती

रियाद । सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिसाइल हमले के कारण अल नासर और नत्तवी फरगना के बीच होने वाला एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। इस मैच में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेल रहे थे। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए इस मिसाइल हमले के कारण मैच में बाधा आई। सऊदी रक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई से मिसाइल को सफलतापूर्वक हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई और मैच आखिरकार खेला जा सका। इस मुकाबले में अल नासर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की, जिसमें स्वयं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी एक गोल दागकर अपनी टीम की जीत में अहम योगदान दिया। स्थानीय समयानुसार अल-अव्वल पार्क में रात 9-15 बजे शुरू होने वाले इस मैच से ठीक पहले, रियाद में धमाकों की तेज आवाजें सुनाई दीं, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों रशकों और खिलाड़ियों को चिंता में डाल दिया। इस दौरान, लोगों के मोबाइल फोन पर हवाई हमले के खतरे का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें उन्हें शांत रहने, अपने घरों में रहने या सुरक्षित स्थानों पर जाने, नागरिक सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और खड़कियों व दरवाजों से दूर रहने की सलाह दी गई। इस अप्रत्याशित और तनावपूर्ण स्थिति के कारण मैच को तुरंत रोक दिया गया।



निखारें चेहरा संवारें अपना भविष्य

पार्टियों में जाने के लिए किए जाने वाले मेकअप से लेकर कलाकारों के मेकअप तक इसकी उपयोगिता से सभी परिचित हैं, लिहाजा यह मेकअप करना शौक भी हो सकता है और एक कामयाब करियर भी । एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक करियर के रूप में इसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब बाजार के बड़े-बड़े नामों ने इसमें सम्मान जोड़ दिया है । कुछ कामयाब नाम हैं – शहनाज हुसैन, भारती तनजा, वंदना लुथरा, ब्लॉसम कोचर, सिल्वी इत्यादि । इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की और आज बिजनेस ब्रांड के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं । यही वजह है कि अब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर करियर बनाने के इच्छुक युवा ट्रेनिंग लेने लगे हैं, ब्यूटी चैन में अच्छी जॉब उन्हें मिलने लगी है और कम पूंजी में खुद का व्यवसाय शुरू करने लगे हैं । आज मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ फैशन मॉडल्स अथवा फिल्मी सितारों की ही जरूरत नहीं है । दूसरी जगहों पर भी इसकी खास डिमांड है । खासकर शादी के सीजन में इन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है । अब तो इसमें भी स्पेशलाइजेशन हो गया है, जैसे कोई सिर्फ दूल्हे का मेकअप करता है तो कोई दुल्हन का । यहां आपको यह बता दें कि हर माध्यम के लिए अलग-अलग मेकअप होता है । टीवी/फिल्मी कलाकारों का मेकअप अलग होता है तो थिएटर में काम करने वालों का अलग । स्टेज आर्टिस्ट का मेकअप टीवी आर्टिस्ट की तुलना में चटक होगा । किसी कैरेक्टर को उसकी उम्र से अलग दिखाना है तो उसका मेकअप अलग होगा, वहीं जले या दाग दिखाने के लिए मेकअप अलग होगा । शहर और वहां की जलवायु के मुताबिक भी मेकअप किया जाता है । जैसे मुंबई में हवा में नमी रहती है, इसलिए पसीने को ध्यान में रख कर ऐसा मेकअप करना पड़ता है कि वह खराब न हो । वहीं राजस्थान में मेकअप के लिए अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है । यह तभी संभव है, जब मेकअप आर्टिस्ट को इसका ठीक-ठीक ज्ञान हो कि स्थान, उम्र और जरूरत के लिहाज से कैसा मेकअप होना चाहिए ।

गुण क्या हो ?

इस प्रोफेशन में भी करियर बनाने के लिए कुछ विशेष गुणों की दरकार है । सबसे पहले उसमें विजुअलाइजेशन की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा स्टाइल या गेटअप किस पर फबेगा । उसे ऐसा रूप देना कि खुद को देख कर उसमें आत्मविश्वास भर जाए । कभी-कभी कई घंटों तक काम करना होता है, खासकर टीवी और फिल्म की शूटिंग के दौरान । शारीरिक और मानसिक रूप से उसका फिट होना बहुत जरूरी है, तभी वह अपने काम को सही-सही अंजाम दे पाएगा । आप में रंग और उसके असर की बारीक समझ होनी चाहिए । मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपका व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए, तभी जिसका आप मेकअप करने जा रहे हैं, उसे बिना उबाए या थकाए उसका मनपसंद गेटअप आप उसे दे पाएंगे । इसके अलावा खुद भी आकर्षक दिखना जरूरी है । फैशन इंडस्ट्री में स्टाइल और ट्रेंड रोज बदलते हैं, इसलिए नई-नई तकनीक, हेयरस्टाइल्स और कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट के बारे में उसे अपडेट रहना होगा ।

योग्यता क्या हो ?

मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है और न ही किसी प्रकार की योग्यता की । इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्कूल या कॉलेज में कौन सा विषय लिया था । बस आप में इस काम के प्रति लगाव होना चाहिए । अगर ऐसा है तो आपके लिए करियर की राहें आसान हैं । अगर 10वीं या 12वीं पास हैं तो और भी बेहतर । इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आप ब्यूटीकेयर के अंतर्गत अन्य विषयों जैसे ब्यूटीशियन, मैनिच्यूरिस्ट, पैडिक्यूरिस्ट, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट व अरोमा थेरेपी विषयों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं । इसके अलावा आप किसी संस्थान से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर

मेकअप आर्टिस्ट किसी जवान इंसान को बूढ़ा बना देता है तो बूढ़े इंसान को जवान । यही नहीं, मेकअप में वो ताकत है, जो चरित्र के हिसाब से कलाकार का पूरा व्यक्तित्व बदल दे । सुंदर दिखने-दिखाने की चाहत व्यक्तिगत रुचि से लेकर व्यावसायिक कौशल तक फैली हुई है । यही कारण है कि मेकअप करना एक खास किस्म का हुनर है ।

सकते हैं । संस्थानों द्वारा संचालित कोर्सज के पाठ्यक्रम में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डाइट, सेल्समेनशिप व सेलून आर्गेनाइजेशन से संबंधित थ्योरी पढ़ाई जाती है । वहीं प्रैक्टिकल वर्क के रूप में फेशियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, मेकअप व इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट सिखाया जाता है ।

नौकरी के अवसर

वर्तमान में फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री में मेकअप व हेयर ड्रेसिंग एक्सपर्ट की मांग बढ़ती जा रही है । इन एक्सपर्ट्स को फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है । बतौर फीलांस भी इसमें हैं ढेरों काम । फैशन आर्गेनाइजर, ब्यूटी पार्लरों, सिलेब्रिटीज के लिए बड़े पैमाने पर काम है ।

वेतन

इस क्षेत्र में आने वाले को बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता । प्रशिक्षण और इंटरनशिप के दौरान ही आपकी कमाई होक लगती है । शुरुआती सैलरी 8 से 10 हजार मिलती है, लेकिन 5 साल के भीतर आप हर महीने 30 हजार रुपये तक कमा सकते हैं । एक बार आपका नाम हो गया तो आकाश ही सीमा है । कुछ कलाकार साल में 5 लाख रुपये या इससे अधिक भी कमा लेते हैं । वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन एजेंसी द्वारा शुरू की गई कंपेन में एक दिन में ही आपकी कमाई 1500 से 3000 रुपये तक हो सकती है ।

कहां-कहां हैं मौके ?



फिल्म/ टीवी/ वीडियो/ रंगमंच/ फैशन/ विज्ञापन एजेंसियों में तो बेशुमार जॉब हैं ही, तेजी से खुल रहे न्यूज चैनलों में भी मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड है । वर्तमान में फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री में मेकअप व हेयर ड्रेसिंग एक्सपर्ट की मांग बढ़ती जा रही है । इन एक्सपर्ट्स को फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है । फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि स्टूडियो की चकाचौंध लाइट में एक्टर का मेकअप कैसे किया जाता है । बतौर फीलांस भी इसमें हैं ढेरों काम । फैशन आर्गेनाइजर, ब्यूटी पार्लरों, सिलेब्रिटीज के लिए बड़े पैमाने पर काम है ।



यूपीएससी हर साल सिविल सेवा में परीक्षा का आयोजन करता है । इनमें आईएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस पदों के लिए सबसे ज्यादा दावेदार होते हैं । इस परीक्षा को क्रैक कर आईएस की तरह आईएफएस अफसर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है । क्योंकि एक आईएस जहां देश के अंदर कार्य करता है, वहीं एक आईएफएस ऑफिसर दूसरे देशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है । इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए और इनका क्या काम होता है ।

कौन और कैसे बन सकते हैं आईएफएस ऑफिसर

आईएफएस स्तर का अधिकारी देश का प्रतिनिधित्व अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर करता है ।

इनका दायरा एक आईएस ऑफिसर से बड़ा होता है । क्योंकि जहां एक आईएस जिले व देश तक सीमित होते हैं, वहीं एक आईएफएस देश स्तर पर अधिकारिक रूप में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओ और देशों के साथ काम करते हैं । इनके काम का असर सीधा देश पर पड़ता है । आईएफएस के लिए भी उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन आईएफएस की मुख्य परीक्षा का सिलेबस अन्य परीक्षाओं से अलग होता है । आईएफएस में आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक आईएफएस ऑफिसर विभिन्न देशो के राजदूत, अधिकारी व नेताओं से बात करनी होती है तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और बोलचाल में जरूरत होती है ।

एलिजिबिलिटी

क्राइटेरिया

राष्ट्रीयता

आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार की राष्ट्रीयता निम्नलिखित होनी चाहिए

- भारत के नागरिक हो
- नेपाल/भूटान की नागरिक हो
- वे तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले स्थायी रूप से बसने के लिए यहाँ आए, या
- भारतीय मूल के वे लोग जिन्होंने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए युगांडा, बर्मा, पाकिस्तान, जाम्बिया, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, मलावी, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास किया ।

शैक्षणिक योग्यता

- उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए ।

आयु सीमा

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना में यूपीएससी आयु सीमा 2022 की जानकारी जारी की गई है । आयु सीमा पात्रता मानदंड के अनुसार, 1 अगस्त 2022 को 21 से 32 वर्ष के बीच की आयु के लोग यूपीएससी एग्जाम में आवेदन पत्र भर सकते हैं । आरक्षित वर्ग के आवेदक यूपीएससी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयु में छूट के पात्र होते हैं ।



- एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए – 5 साल
- ओबीसी उम्मीदवारों के लिए – 3 साल ।
- जम्मू और कश्मीर राज्य के उम्मीदवार के लिए – 5 वर्ष
- रक्षा सेवा कर्मियों के लिए – 5 वर्ष
- पूर्व सैनिक जिनमें कमीशन अधिकारी और ईसीओ/एसएससीओ शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 5 साल की सेन्य सेवा प्रदान की है और उन्हें रिहा कर दिया गया – 5 वर्ष
- नेत्रहीन, मूक-बधिर और विकलांग व्यक्तियों के लिए – 10 वर्ष

उम्मीदवार कितनी बार दे सकते हैं ये एग्जाम

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार – 6 प्रयास
- एससी/एसटी के उम्मीदवार – कोई प्रतिबंध नहीं
- अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार – 9 प्रयास
- सामान्य व ओबीसी दिव्यांग – 9 प्रयास

मेडिकल स्टैंडर्ड

इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले आवेदकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए । यूपीएससी सीएसई पर्सनालिटी टेस्ट के बाद चुने गए उम्मीदवार यूपीएससी द्वारा अधिसूचित चिकित्सा केंद्र में मेडिकल टेस्ट से गुजरते हैं । किसी भी सेवा में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को सभी मेडिकल टेस्ट पास करना होता है ।

आईएफएस के कार्य

एक आईएफएस का काम उसके उसकी प्रोफाइल पर निर्भर करता है । विदेश में रह रहे भारतीयों की मदद वहां का भारतीय दूतावास करता है, जोकि एक आईएफएस का कार्य होता है । यही ऑफिसर राजदूत और राजनयिक के रूप में भी कार्य करते हैं । इनका मुख्य कार्य दोनों देशो के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना और अन्य किसी प्रकार के वाद-विवाद को भी बातचीत के जरिए हल करना है । साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनाइटेड नेशन व अन्य प्लेटफार्म आईएफएस अधिकारी ही विदेशी मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसके साथ ही भारत की सुरक्षा व विदेशी नीति मामलों में भी इन्हें आईएफएस की मदद ली जाती है और ये अपने अनुभव से देश की विदेश सुरक्षा पॉलिसी में अपने विचार व ज्ञान का उपयोग करते हैं ।



ऑडियो इंजीनियरिंग नई पीढ़ी का उभरता हुआ करियर

एक समय ऐसा था, जब आवाज को उसके मूल रूप में ही रिकॉर्ड किया जाता था, परन्तु आज उसमें काफी हद तक बदलाव लाया जा सकता है । यह सब संभव हो पाया है ‘ ऑडियो इंजीनियरिंग ’ से । वैसे तो आवाज या म्युजिक का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते-आते उसमें कई चीजें जुड़ गईं । ऑडियो इंजीनियरिंग, ऑडियो साइंस की ही एक शाखा है । इसमें साउंड के कैचर करने, रिकॉर्डिंग करने, कोपी करने, एडिटिंग एवं मिक्सिंग करने, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल उपकरणों द्वारा आवाज में उतार-चढ़ाव लाने संबंधी कार्य किए जाते हैं । यह पूरा कार्य पोस्ट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है । इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग बोर्ड लगा होता है, जिससे रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग प्रक्रिया में साउंड इनपुट जैसे स्विच, डायल, लाइट्स एवं मीटर को नियंत्रित किया जाता है । यह कार्य ऑडियो इंजीनियर के जरिए संपन्न किया जाता है । कई बार इन्हें रिकॉर्डिंग इंजीनियर या साउंड इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है । ऑडियो इंजीनियरिंग नई पीढ़ी के लिए एक उभरता हुआ करियर है, जो भारत एवं विदेश दोनों जगह फिल्म, वीडियो प्रोडक्शन, साउंड ब्रॉडकास्टिंग एवं एडवर्टाइजिंग में संभावनाएं तलाशता है । इस फील्ड के लिए खुद से कमिटमेंट एवं इंटरेस्ट होना आवश्यक है ।

कालिफिकेशन

एक सफल ऑडियो इंजीनियर बनने के लिए ऑडियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग एवं ऑडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा डिग्री कोर्स का होना आवश्यक है । वैसे तो इस फील्ड में किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की दरकार नहीं होती, परन्तु ऑडियो इंजीनियरिंग में बेवचर अथवा पीजी डिग्री को वरीयता दी जाती है । जहां तक डिमांड की बात है तो ऑडियो इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स अथवा मैथ्स की आधारभूत जानकारी सहायक साबित होती है, जिसके दम पर वे रिकॉर्डिंग रूम में कई तरह की अधिक प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर एक अच्छा ऑडियो इंजीनियर बना जा सकता है । जिन छात्रों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं फाइन आर्ट की पृष्ठभूमि रही है, वे भी इस कोर्स के लिए उपयुक्त साबित हो सकते हैं । साथ ही उन्हें रिकॉर्डिंग उपकरणों जैसे मिक्सिंग कंसोल्ड एवं माइक्रोफोन की जानकारी भी होनी चाहिए । इस कार्य में उन्हें डिजिटल ऑडियो स्टेशन, स्पीकर, एप्लीफायर सहित कई अन्य म्युजिक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है ।

कोर्स डिटेल्स

ऑडियो इंजीनियरिंग में साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एवं मिक्सिंग के तकनीकी एवं रचनात्मक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है । इसमें अधिकतर कोर्स की शुरुआत ही साउंड एवं रिकॉडिंग, पोस्ट प्रोडक्शन एवं ब्रॉडकास्टिंग की आधारभूत थ्योरी एवं फिक्ंसी से की जाती है । इसके तकनीकी पहलुओं के अंतर्गत ही साउंड मिक्सिंग में स्पेशल इफेक्ट्स डाला जाता है । कोर्स के बाद छात्र रिकॉर्डिंग टूल्स, माइक्रोफोन के प्रयोग के बारे में अच्छी तरह से वाकफ हो जाते हैं । इसके अलावा ऑडियो राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक



ऑडियो इंजीनियरिंग भारत

एवं विदेश दोनों जगह

फिल्म, वीडियो प्रोडक्शन,

साउंड ब्रॉडकास्टिंग एवं

एडवर्टाइजिंग में संभावनाएं

तलाशता है । इस फील्ड के

लिए खुद से कमिटमेंट एवं

इंटरेस्ट होना आवश्यक है।

म्युजिक, साउंड रिकॉर्डिंग, म्युजिक बिजनेस, मल्टीट्रैक प्रोडक्शन आदि कई ऐसे एरिया हैं, जिन्हें ऑडियो इंजीनियरिंग के तहत शामिल किया जाता है ।

पर्सनल स्किल्स

एक ऑडियो इंजीनियर को टेविनकल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल एप्टीट्यूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सिस्टम एवं इंक्रिपमेंट की जानकारी होनी आवश्यक है । म्युजिक प्रोडक्शन में टीम वर्क, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काम को गति दे सकते हैं । एकाग्रता, धैर्य, अच्छी समझ, अच्छी लय की जरूरत, अच्छी रिश्ता जैसे गुण ऑडियो इंजीनियर के लिए आवश्यक हैं । साथ ही उसे रिकॉर्डिंग माध्यमों जैसे एनालॉग टेप, डिजिटल मल्टीट्रैक रिकॉर्डर एवं कम्यूटर नॉलेज की जानकारी भी सहायता दिला सकती है ।

नौकरी के अवसर

इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ऑडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री पहली सीढ़ी होती है । सफलतापूर्वक कोर्स करने के बाद मूवी, टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग, मल्टीमीडिया संस्थान, ब्रॉडकास्टिंग, सीडी प्रोडक्शन आदि में जॉब पा सकते हैं । लेकिन एक ऑडियो इंजीनियर को जो फील्ड सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वह म्युजिक इंडस्ट्री है । इसमें प्रारंभ में रिकॉर्डिंग इंजीनियर के सहायक के रूप में करियर आरंभ कर सकते हैं । अपने अनुभव के आधार पर जल्द ही वे ऑडियो इंजीनियर के पद पर पहुंच सकते हैं । इसके अतिरिक्त माइक्रोफोन, रिकॉर्डर, मिक्सर एवं सॉफ्टवेयर, म्युजिक एवं स्पीच में कई तरह के काम सामने आते हैं । साउंड, म्युजिक, डायलॉग, स्पेशल इफेक्ट्स, म्युजिक प्रोड्यूसर को भी स्पेशलाइजेशन के रूप में अपनाया जा सकता है । म्युजिक प्रोड्यूसर बनने के बाद खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी शुरू किया जा सकता है । स्टूडियो स्थापित करने के अलावा ऑडियो इंजीनियर फीलांस के रूप में भी काम कर सकते हैं । ऑडियो इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफी प्रतियोगी है । इसमें वही लोग सफल हो सकते हैं, जिनमें टैलेंट एवं विशेष गुण हैं ।

सेलरी स्ट्रक्चर

बतौर ऑडियो इंजीनियर इनकी सेलरी 10,000 रुपए प्रतिमाह से शुरू होती है तथा मान्यता मिल जाने के बाद इनकी सेलरी में तेजी से इजाफा होता है । तीन से चार साल के अनुभव के बाद इनकी सेलरी 30- 35 हजार रुपए तक पहुंच जाती है । विदेशों में जॉब के अवसर मिलने के बाद सेलरी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती ।

उत्तर और दक्षिण कोरिया में बढ़ा तनाव: किम जोंग उन ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइले

सिओल , एजेंसी। उत्तर कोरिया ने सोमवार को अपने पूर्वी समुद्री इलाके की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यह जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना ने दिया। यह हाल के दिनों में हथियारों के प्रदर्शन का एक और मामला है, जिससे कूटनीतिक बातचीत लंबे समय से रुकी होने के बीच तनाव और बढ़ गया है।

जॉइंट चीफ्स ऑफ़ स्टाफ ने क्या बताया? – दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ़ स्टाफ ने बताया कि मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आस-पास के इलाके से दागी गईं। हाल के वर्षों में देश ने अपने हवाई अड्डे का इस्तेमाल एक मुख्य लॉन्च साइट के तौर पर किया है। जॉइंट चीफ्स ने तुरंत यह नहीं बताया कि कितनी

मिसाइलें देखी गईं या वे कितनी दूर तक गईं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने कम से कम दो मिसाइलें देखीं और अनुमान लगाया कि ये हथियार देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर समुद्र में गिर।

दक्षिण कोरिया ने किया हथियार के उड़ान परीक्षण– यह लॉन्च दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने पहले घरेलू स्तर पर विकसित हाइपरसोनिक हथियार के उड़ान परीक्षण के कुछ दिनों बाद किया। इस हथियार को ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना तेज उड़ने और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने इसे दक्षिण कोरिया की पारंपरिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।



उत्तर कोरिया क्यों कर रहा इतने परीक्षण?– सियोल के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए, उत्तर कोरिया अपने परमाणु-सक्षम हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के लिए लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इसमें 3 अक्तूबर को किया गया वह परीक्षण भी शामिल है, जिसे उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट-रेंज मिसाइल बताया था। इसे दक्षिण कोरिया और जापान की मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है।

उत्तर कोरिया ने मिसाइल के और भी टेस्ट किए हैं, लाइव-फायर ड्रिल की हैं और एक नया युद्धपोत भी शामिल किया है। नेता किम जोंग-उन अपने परमाणु

हथियार कार्यक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लंबे समय से रुके हुए कूटनीतिक बातचीत को फिर से शुरू करने के प्रस्तावों को भी ठुकरा रहे हैं।

दक्षिण कोरिया के तीन सैनिक कैसे घायल हुए? – पिछले महीने भारी हथियारों से लैस अंतर-कोरियाई सीमा के पास लैंड माइन धमाकों में दक्षिण कोरिया के तीन सैनिकों के घायल होने के बाद तनाव और बढ़ गया। दक्षिण कोरिया की सेना और अमेरिका के नेतृत्व वाली यूनाइटेड नेशंस कमांड ने निष्कर्ष निकाला कि ये धमाके उत्तर कोरिया की ओर से लगाए गए उपकरणों के कारण हुए थे। हालांकि, उत्तर कोरिया ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है

और माफी की दक्षिण कोरिया की मांग का मजाक उड़या है।

हाल के वर्षों में, वॉशिंगटन के साथ परमाणु बातचीत में लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बीच, किम ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी तरह की कूटनीति और सहयोग रोक दिया है और पड़ोसी देश को अपना पक्का दुश्मन बताया है। उन्होंने अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत फिर से शुरू करने की अपील को ठुकरा दिया है। 2019 में यह बातचीत टूट गई थी। उनकी सरकार की मांग है कि वॉशिंगटन प्योंगयांग के प्रति अपनी दुश्मनी वाली नीति छोड़े और बातचीत के लिए शर्त के तौर पर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार खत्म करने की मांग को हटाए।

संक्षिप्त

समाचार

भावनाओं को समझने में महिलाएं आगे, पर यही खूबी बन जाती है उनके लिए बड़ा बोझ

ज्यूरिख, एजेंसी। किसी बैठक में सहकमी का अचानक चुप हो जाना, किसी दोस्त के चेहरे से उसकी परेशानी भांप लेना या तनाव के बीच सही बात कहकर माहौल संभाल लेना। ये ऐसे कौशल हैं, जो रिशतों को बेहतर बनाने के साथ कामकाज को भी आसान करते हैं।

लेकिन जब इन्हें किसी की स्वाभाविक खूबी मान लिया जाता है, तो यही क्षमता उसके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी बन सकती है। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा ही होता है।

लिमरिक विश्वविद्यालय की मैरी एम हाउसफेल्ड और ज्यूरिख विश्वविद्यालय के योखेन मिंगेस ने 1995 से 2023 तक प्रकाशित शोधों की समीक्षा की। इसमें 76 देशों के छह लाख से अधिक लोग शामिल थे।



अध्ययन में औसतन महिलाओं का भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर पाया गया। यह बहुत खास तौर पर दूसरों की भावनाओं को पहचानने, उनके कारण समझने और उनसे निपटने में मदद करने के मामले में दिखी। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि हर महिला इस मामले में हर पुरुष से बेहतर होती है। **बचपन से मिलता है ज्यादा अभ्यास**– भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और संभालने की क्षमता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इसकी एक वजह बचपन में लड़के-लड़कियों की परवरिश का अंतर हो सकता है। माता-पिता अक्सर बेटियों को भावनाओं पर बात करने और उन्हें शब्दों में व्यक्त करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, जबकि बेटों को कई बार भावनाएं दबाने की सीख मिलती है।

इस तरह लड़कियों को दूसरों की भावनाएं समझने और उनके अनुरूप प्रतिक्रिया देने का अधिक अभ्यास मिलता है। जैसे कोई भाषा या वाद्य यंत्र सीखने से उसमें दक्षता बढ़ती है, वैसे ही भावनात्मक कौशल भी अभ्यास से निखरते हैं। वर्ष 2019 में 58 अध्ययनों के मेटा-विश्लेषण में भी पाया गया कि प्रशिक्षण से भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है। समस्या तब शुरू होती है, जब महिलाओं की इस क्षमता को कौशल मानने के बजाय उनकी स्वाभाविक जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। दम्पतर में टीम का तनाव संभालना, परेशान सहकमी को सहारा देना और विवाद शांत करना अक्सर उन्हीं के हिस्से आता है। इससे कामकाज सुचारु रहता है, लेकिन प्रदर्शन के आकलन और पुरस्कारों में इस योगदान को जगह नहीं मिलती।

अमेरिका-ब्रिटेन में पढ़ा रहे पाकिस्तानी शिक्षाविदों ने उठाई आवाज, इमान मजारी और उनके पति को रिहा करे पाकिस्तान

लंदन, एजेंसी। पाकिस्तान में वकील इमान ज़ैनब मजारी-हाज़िर और हदी अली चड्ढा की हिरासत को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में कार्यरत पाकिस्तानी मूल के शिक्षाविदों ने आवाज उठाई है। उन्होंने दोनों वकीलों के खिलाफ आरोप वापस लेने और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। शिक्षाविदों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के शासन से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। लाहौर में जारी संयुक्त बयान में शिक्षाविदों ने पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन की स्थिति पर चिंता जताई। यह बयान जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के आकिल शाह की पहल पर जारी किया गया।

बयान के मुताबिक, जनवरी 2026 में इमान मजारी और हदी चड्ढा को सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून (पीईसीए) के तहत 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इन पोस्ट में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की



आलोचना की गई थी। शिक्षाविदों के अनुसार, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें वमानत दे दी थी। हालांकि, कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने एक अन्य मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया। संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों अब भी हिरासत में हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि इमान मजारी जबरन ग़ुमशुगी के मामलों पर आवाज उठाती रही है और पीड़ितों तथा उनके

परिवारों का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर संस्थानों की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी की है। वहीं, हदी चड्ढा ने ईशनिंदा के आरोपों का सामना कर रहे लोगों और मृत्युदंड पाए कैदियों का बचाव किया है। बयान में कहा गया कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल असहमति की आवाज दबाने या वकीलों को उनकी पैरवी के कारण डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान को विश्व बैंक का झटका: दक्षिण एशिया की सूची से नाम बाहर, भारत से तुलना खत्म होने पर मचा बवाल

न्यूयार्क, एजेंसी। विश्व बैंक के क्षेत्रीय वर्गीकरण में बदलाव को लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी पत्रकार शहबाज राणा के मुताबिक, पाकिस्तान को दक्षिण एशिया समूह से हटाकर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रूख़ढ़्क़ समूह में शामिल किया गया है। हालांकि, इसे भारत की जीत या पाकिस्तान को दंडित करने का फैसला बताने के लिए ठोस प्रमाण सामने नहीं हैं। यह बदलाव विश्व बैंक की प्रशासनिक और क्षेत्रीय व्यवस्था से जुड़ा है।

विश्व बैंक के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 1 जुलाई 2025 से दक्षिण एशिया की श्रेणी से हटाकर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में शामिल किया गया। इस बदलाव की पुष्टि विश्व बैंक के आँकड़ा पोर्टल और उसके दिसंबर 2025 के लेख में भी की गई है। दक्षिण एशिया के इस नए वर्गीकरण में अब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल हैं।



पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग क्षेत्रीय समूह में रखा गया है। पाकिस्तानी पत्रकार शहबाज राणा ने अपने कार्यक्रम में इस बदलाव को भारत-पाकिस्तान तनाव और विश्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी परिस्थितियों से जोड़कर चर्चा की। उनके अनुसार, नई दिल्ली में कार्यालय होने की स्थिति में पाकिस्तानी अधिकारियों को वीजा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। क्षेत्रीय वर्गीकरण बदलने से पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति या उसकी आय के आधार पर तय होने वाली आर्थिक श्रेणी अपने आप नहीं बदलती।

सरकारी खजाने से ट्रंप का प्रचार पड़ा भारी जनता के पैसों से चल रहे विज्ञापनों पर कोर्ट ने लगाई रोक

वाशिंगटन एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने राजनीतिक संदेश के प्रचार के लिए सरकारी खजाने से चलाए जा रहे टीवी विज्ञापनों पर रोक लगानी होगी। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने रविवार रात प्रशासन को आदेश दिया कि ऐसे सभी विज्ञापन तुरंत बंद किए जाएं, जो अब भी प्रसारित होने बाकी हैं। खास बात यह है कि प्रशासन पहले ही कह चुका था कि विज्ञापन अभियान जल्द खत्म होने वाला है। इसके बावजूद अदालत ने साफ कर दिया कि रविवार रात प्रसारित होने वाले विज्ञापनों समेत बाकी सभी विज्ञापनों को भी रद्द करना होगा।

जनता के पैसे से राजनीतिक प्रचार पर उठे सवाल– यह पूरा मामला उन टीवी विज्ञापनों से जुड़ा है, जिन पर करदाताओं के लाखों डॉलर खर्च किए गए। इन विज्ञापनों के जरिए ट्रंप के राजनीतिक संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इस खर्च पर सवाल उठते हुए एक गठबंधन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस गठबंधन में गैर-दलीय निगरानी संगठन कॉमन कॉज भी शामिल था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकारी धन का इस तरह इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ



अब सरकारी खर्च और राजनीतिक संदेश के इस्तेमाल पर नजर

इस मामले ने सरकारी धन के इस्तेमाल और राजनीतिक प्रचार के बीच की सीमा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत करने वाले संगठनों का कहना है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता, जिसे वे किसी राजनीतिक संदेश को बढ़ावा देने का अनुचित तरीका मानते हैं। अदालत के आदेश का तत्काल असर यह है कि प्रशासन को बचे हुए विज्ञापनों को रोकना होगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह आदेश अस्थायी रोक के तौर पर जारी किया गया है। मामले में आगे क्या होता है, यह न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरणों पर निर्भर करेगा।

अमेरिका में राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी, मिडटर्म चुनाव में क्यों बदला भारतीय-अमेरिकियों का प्लान?

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और प्रवासी भारतीयों के खिलाफ नीतियों ने राजनीतिक दमखम रखने वाले भारतीय प्रवासियों को नए सिरे से अमेरिकी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के पुरजोर प्रयासों के लिए प्रेरित किया है। इसलिए अब भारतीय-अमेरिकी केवल सांसद बनकर अमेरिकी सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीन नवंबर को होने वाले मध्यस्थ चुनाव में अपने मुद्दों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अन्य उम्मीदवारों का भी समर्थन कर रहे हैं।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेताओं ने कहा कि कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में मजबूत मौजूदगी के बावजूद समुदाय के भीतर की प्रतिस्पर्धा के कारण निर्वाचित पदों



पर भारतीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कम रहा है। प्रवासी समुदाय के एक नेता ने कहा,ऐसे मौके आए हैं जब कई भारतीय-अमेरिकी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। इससे समुदाय के उम्मीदवारों की कम संख्या में जीत हुई।

उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए एकजुटता पर जोर

दिया। कार्यकाल पूरा कर रही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारतीय मूल के छह सदस्य हैं, लेकिन यह संख्या घटकर चार रह सकती है। इलिनोइस से राजा कृष्णमूर्ति और मिशिगन से श्री थानेदार प्रलमरी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके।

भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना (कैलिफोर्निया-17), प्रमिला जयपाल

(वाशिंगटन-7), एमी बेरा (कैलिफोर्निया-3) और सुहास सुब्रमण्यम (वर्जीनिया-10) फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में मैदान में हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होने वाले मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों और ऊपरी सदन सीनेट के 100 सदस्यों में से करीब एक-तिहाई का चुनाव होता है। इन चुनावों में कई राज्यों के गवर्नर व विधानसभाओं के साथ कुछ शहरों के मेयर और अन्य स्थानीय अधिकारियों के चुनाव भी शामिल होते हैं। नतीजे तय करते हैं कि कांग्रेस पर किस दल का नियंत्रण होगा और राष्ट्रपति की विधेयक पारित करने की क्षमता पर भी उनका असर पड़ सकता है।

वांज में निर्माणों का राफड़ा ?

चार साल में 200 से अधिक इमारतों का दावा
10 हजार से ज्यादा श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल



क्रांति
समय
Information you

जांच पड़ताल
ख़ास रिपोर्ट

वांज में निर्माणों का
राफड़ा ?

**200 से अधिक इमारतों का दावा,
10 हजार श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल!**

चार साल में बड़े पैमाने पर निर्माण! सुडा और ग्राम पंचायत की निगरानी पर सवाल—मंजूरी, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच कब?

सुडा से सवाल:

मंजूरी और निरीक्षण का रिकॉर्ड कहाँ?

ग्राम पंचायत से सवाल:

पानी और स्वच्छता की जांच कब?

जिला प्रशासन:

संयुक्त जांच होगी?

आंकड़ों और कथित अनियमितताओं की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक।